implementation of the Programme is reviewed periodically by the Central Committee as well as the Department of Rural Development.

Under the programme State/UT Governments are required to formulate specific work projects. These project proposals are examined in the Department and placed before the Central Committee on NREP/RLE GP for consideration and approval. The State/UT Government can commence work only after the project submitted by them are approved by the Central Committee. However, from the year 1985-86 priority has been given to social forestry by earmarking 20 per cent for social forestry and exemption in this regard has been granted to the State/UT Governments in respect of social forestry projects. The State/UT Governments have been permitted to implement these projects in anticipation of the approval of the Central Committee.

Off-take of foodgrains from the public Distribution System

1301. SHRI SURAJ PRASAD:

SHRI INDRADEEP SINHA:

Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the off-take of foodgrains from the public distribution system has declined;

(b) what was the off-take during the years 1983-84, 1984-85, and 1985-86; and

(c) what steps are being taken to increase the lifting of foodgrains by public distribution system?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) The off-take of foodgrains from public distribution system in the year 1984-85 registered a fall in relation to the 1983-84 level.

(b) The total off-take of foodgrains from public distribution system was 12.29 million tonnes in 1983-84, 9.40 million tonnes in 1985-86 and 5.97 million tonnes in 1985-86 (upto October, 1985).

(c) (1) The monthly allocations of foodgrains for public distribution system have been liberalised;

(2) The State Governments have been advised to stream-line the public distribution system so as to take in more wheat and even to issue wheat to the cardholders through the fair price shops without any ceiling on quantity upto 31st March 1986.

(3) It has also been decided to distribute foodgrains, mostly wheat, at specially subsidized rates to the people living in the tribal areas and other vulnerable sections of the society.

TV staff working for private Organisations

1302. SHRI KAPIL VERMA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of T.V. employees are working for private organisations producing sponsored programmes for T. V. and are being paid for it, if so, what is their number and what is the reason for allowing them to take up this commercial work; and

(b) whether it is a fact that T.V. cameramen at various stations are doing private commercial work, if so, what is their number?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI V. N. GADGIL): (a) In all, three such specific cases have come to the notice of Doordarshan. Whereas the contract of one of the persons involved has since been terminated, action has been initiated against the remaining two for having reportedly accepted outside work without obtaining prior

permission of the competent authority.

(b) Seven Cameramen are reported to have accepted outside commercial work including, commercial films without obtaining the prior permission of the competent authorty.

बिहार में कृषि विज्ञान केन्द्र

1303. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कुल कितने कृषि केन्द्र हैं और वे किस तरीके से कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या मुंगेर जिले के कृषि विज्ञान केन्द्र में अभी भी विशेषज्ञों तथा संसाधनों की कमी है और यदि ह , तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) बरियारपुर के "बिन्दा दियारा" में इसका उप-केन्द्र स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं विशेष रूप से जबकि यह केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह कार्य कर रहे ह लेकिन इस केन्द्र को शहरी क्षेत्रों से स्थानान्तरित नहीं किया गया है; और

(घ) क्या बिन्दा दियारा में "परवल" सब्जी पर व्यावहारिक वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य कराया जाएगा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा): (क) बिहार में 3 कृषि विज्ञान केन्द्र कार्य कर रहे हैं। ये केन्द्र कार्य के विभिन्न स्तरों पर हैं जो उनकी कार्य-अवधि, अपने-अपने मेजबान संस्थान से प्राप्त भवनों, औजार आदि से सम्बन्धित अवस्थापन सुविधाओं और इस परियोजना के अन्तर्गत विकसित बुनियादी सुविधाओं पर निर्भर करते हैं ।

(ख) जी नहीं श्रीमन् ।

(ग) कृषि विज्ञान केन्द्रों के उपकेन्द्र स्थापित करने का कोई प्रावधान नहीं है । "बिन्दा दियारा" के किसानों के प्रशिक्षण की आवश्यकता मुंगेर के कृषि विज्ञान केन्द्र से पूरी हो सकती है ।

(घ) कृषि विज्ञान केन्द्र व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं इसलिए अपने कार्य क्षेत्र में उन्हें किसी प्रकार के अनुसंधान संबंधी अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी जाती फिर भी, दियारा क्षेत्र में परवल के अनुसंधान संबंधी कार्यों की देख-रेख राजेन्द्र कृषि विश्वविधालय, पूसा, समस्तीपुर द्वारा की जा रही है।

समाचार एजेन्सियों को विज्ञापन तथा सहायता

1304. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी और अंग्रेजी की पृथक पृथक कौन-कौन सी समाचार एजेन्सियां सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सूची में शामिल हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक एजेन्सी को कितने-कितने विज्ञापन और अन्य सहायता दी गई ;

(ग) चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक को कितनी और किस प्रकार की सहायता दी गई ;

(घ) किन-किन समाचार एजेन्सियों को दी जाने वाली सहायता कम की गई है या कम की जा रही है ;

(ङ) क्या यह सच है कि हिन्दी समाचार एजेन्सियों को यह सहायता नहीं दी गयी है ; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) समाचार एजेंसियों को सूचीबद्ध करने की कोई प्रणाली नहीं है ।